National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 273-274

दक्षिण एशिया में 'आर्थिक परिसंघ' की संभावना

अमित कुमार सिंह
शोध छात्र (जे0आर0एफ0), राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो गये हैं। राष्ट्रों के आपसी संबंधों में आर्थिक पहलू एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में आर्थिक कारक, राजनीतिक व सामरिक संबंधों पर वरीयता प्राप्त करते जा रहे हैं। राजनीतिक व सामरिक हित भिन्न होते हुए भी राष्ट्रों के आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है। अतः आर्थिक राष्ट्रवाद से आर्थिक भूमण्डलीकरण की ओर बढ़ते विश्व में देश अपने आर्थिक संबंध को पुनः परिभाषित करते हुए सहयोग के क्षेत्र बढ़ाने में प्रयासरत हैं।

मूल शब्द : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक संबंध, राष्ट्रवाद।

प्रस्तावना
अन्य विकासशील देशों की तरह दक्षिण एशियाई देशों में घरेलू झगड़ों एवं समस्याओं का कारण उपयुक्त आर्थिक विकास का नहीं होना है, जिसके कारण नागरिक सामाजिक न्याय से वंचित हो जाते हैं परिणाम स्वरूप पारस्परिक मतभेद एवं ऐसे मतभेदों का जन्म जो न केवल घरेलू विकास प्रक्रिया को अवरूद्ध करते हैं, वरन् आस–पड़ोस के देशों के सम्बन्धों पर गहरा असर डालते हैं। वैसे तो सारे विकासशील राष्ट्रों में असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है, विशेषकर दक्षिण एशिया के सभी सार्क देशों में असमानता और ज्यादा व्याप्त है। आय की वृद्धि उत्पादन के विभिन्न साधनों पर निर्भर करती है जिनका असमान वितरण आय वृद्धि तथा आर्थिक समानता में बाधक है। उदाहरणार्थ भूमि, उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसका वितरण नितांत असंतुलित है। जहाँ तक गरीबी की रेखा का प्रश्न है भारत में अभी भी 26% लोग गरीबी के रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं पाक में यह दर भारत तथा बांग्लादेश से भी अधिक है।

आर्थिक कारकों में गरीबी एक प्रमुख समस्या रही है जिससे गंदगी कुपोषण परिणामस्वरूप तथा औसत उम्र कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी जन्म लेती है जिससे आर्थिक विकास में अन्तर आता है। 1947 के बाद चूँकि बहुत ज्यादा मुस्लिम समुदाय का स्थानान्तरण न होने से वे गरीब ही बने रहे। पाकिस्तान बनने से उनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रबुद्ध वर्ग को जरूर विभाजन का फायदा हुआ। इसलिए पाकिस्तान में भी मुसलमान और गरीब होते गए। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में उद्योगपतियों, नौकरशाही तथा जमीदारों की 'त्रिधुरी' के अधीन उनका उत्तरोत्तर शोषण हो रहा है। समूचे उद्योग–जगत का मानो निजी व्यापारीकरण कर दिया गया हो, जिसमें लाभ एकमात्र उनका लक्ष्य रहता है। यह इसलिए प्रमाणित होता है कि पाकिस्तान में स्वातन्त्रयोत्तर काल में लगभग 43 बड़े उद्योगों प्रतिष्ठानों को निजी कम्पनियों में परिवर्तित कर दिया गया तथा शेष 19 को निजी प्रबन्ध के अधीन कर दिया गया।

पाकिस्तान अपनी पूंजीगत संसाधनों की कमी को वह विदेशी सहायता अनुदान से आपूर्ति करता है तथा सहायता के साथ उसकी आर्थिक नीति की पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों के अनुकूल ही सिमट कर रह जाती जिसका सीधा असर विदेशी नीति पर पड़ता है। पाकिस्तान आज विदेशी सहायता (अमेरिका) पर निर्भर है तथा पाक की आर्थिक स्थिति पूर्णतः विनाश के कगार पर पहुँच गयी है। यही कारण है कि पाकिस्तान अभी तक राष्ट्रीय पहचान बनाने में असमर्थ रहा है। पाकिस्तान में इसी आर्थिक असमानता के कारण बलूची, पठान, सिंधी एवं पंजाबी निरन्तर एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं और कोई ताज्जुब नहीं है यदि यह नीति कायम रही तो एक और विभाजन पाकिस्तान को विभाजन सहना पड़े।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का भी निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। स्वतन्त्रता के पहले श्रीलंका व्यापारोन्मुखी था तथा मध्यमवर्गीय व्यापारियों को प्रोत्साहन देता था। सिंघलियों की अपेक्षा तमिलों को अंग्रेजों द्वारा काफी प्रोत्साहन दिया जाता था जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई, लेकिन 1948 के बाद इस नीति में एकदम बदलाव आ गया। अब बहुसंख्यक वर्ग जिसका राजनीतिक वर्चस्व था को लाभ देने की गरज से संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा तथा अल्पसंख्यक (तमिल) वर्ग की अनदेखी की जाने लगी जिससे आर्थिक जटिलताओं ने जन्म लिया। 1977 के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई अतः अब 'स्वतन्त्र बाजार विकास निर्यात' पर जोर दिया जाने लगा। व्यापार वृद्धि, विदेशी पूंजी निवेश, प्रोत्साहन एवं विदेशी सहायता की निर्भरता पर जोर दिया गया। मुद्रा अवमूल्यन, उदार आयात, मूल्य नियंत्रण आदि कदम भी उठाये गये। इन सबके बावजूद अर्थव्यवस्था पर कोई खास सुधार नजर नहीं आता है।

आर्थिक पतन के कारण कई प्रकार की समस्याओं ने सिर उठाना प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण दक्षिण में तनाव ने जन्म दिया, क्योंकि उनका सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्धों पर असर पड़ता है। श्रीलंका, चाय, रबर तथा नारियल निर्यात करता है लेकिन आश्चर्य तब होता है जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत बढ़ने के साथ चाय का निर्यात बहुत ही कम था। रबड़ का उत्पादन कम होता जा रहा है, दूसरी ओर खाद्य, जिन्स, कपड़ा आदि के आयात में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है जिससे आयात–निर्यात संतुलन बिगड़ रहा है। कमोवेश यही स्थिति नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा मालद्वीव की भी है।

सम्पूर्ण क्षेत्र गरीबी, सतत सामग्री का अभाव, प्रतिकूल व्यापारिक परिस्थितियां, नैसर्गिक संसाधनों का उचित दोहन न हो पाना तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की कमी आदि के अलावा बहुराष्ट्रीय निगमों की संदिग्ध हरकतें एवं अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में निरन्तर कमी आदि आर्थिक जटिलताओं में वृद्धि ही करती प्रतीत होती है। इसके अलावा चाय, जूट, कपास, चावल आदि प्रमुख फसलों हेतु साझा बाजार का न होना तथा क्षेत्रीय आधार पर व्यापारिक क्रय–विक्रय में परस्पर सहभागिता न होना भी आर्थिक समस्याएं खड़ी करता है। उस पर भी पाकिस्तान का इस्लामिक

देशों से आर्थिक प्रगाढ़ता नेपाल तथा चीन के प्रति आकर्षित होना तथा श्रीलंका का अमेरिका सहित पश्चिम तथा 'आसियान' देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध जोड़ना परस्पर क्षेत्रीय मतभेद एवं तनाव को पैदा करने वाली गतिविधियाँ हैं।

इस संदर्भ में एक और समस्या खास उत्पादन क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई देशों के मध्य प्रतिद्वन्दिता का होना, जैसे–चाय (श्रीलंका–भारत), जूट (भारत–बांग्लादेश), सूती कपड़े (भारत–पाकिस्तान), कीमती पत्थर (भारत–श्रीलंका) और चावल (भारत–पाकिस्तान), नारियल (श्रीलंका–भारत–मालद्वीव) इससे आर्थिक हितों की सुरक्षा सम्बन्धी द्वेष बढ़ती है तथा एक देश दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ओत–प्रोत हो जाते हैं तथा संबंधित देश की जिन्सों में आयाती सीमाएं लागू कर देता है। भूटान, नेपाल एवं मालद्वीव कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादकता के अभाव के कारण आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है।

तैयार माल तथा कच्ची सामग्री दक्षिण एशियाई देशों में उतनी उच्च कोटि की नहीं कि वह उपभोक्ताओं को विश्व बाजार में अपनी ओर आकर्षित कर सके क्योंकि तकनीकी आधारों की इन देशों में कमी है। ''बहुराष्ट्रीय नियमों'' ने इन समस्याओं को और आर्थिक बढ़ा दिया क्योंकि उनकी यह एक नियोजित निश्चित नीति है कि वे विकासशील देशों के उत्पादन को हमेशा हतोत्साहित करते हैं जिससे उन्हें आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार की समस्या न हो। इस प्रकार से उस क्षेत्र के देशों की कीमत पर एक बाजार विकसित करते हैं।

उक्त आर्थिक विसमता एवं पिछड़ेपन का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर पड़ता है। इस क्षेत्र के समस्त देश, विदेश ऋणभार, तकनीकी विशेषज्ञता, साझा–बाजार, आयात–निर्यात में असंतुलन के कारण पश्चिमोन्मुखी आर्थिक नीति अपनाने को विवश है तथा इस दृष्टि से इस क्षेत्र में हम क्षेत्र से बाहर की शक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करते हैं तथा वे अपने हितों को दृष्टिगत रखते हुए कर्ता–धर्ता तथा प्रबन्धक दोनों बन जाते हैं तथा आगे चलकर राजनीतिक हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो जाते हैं।

इस दृष्टि से दक्षिण एशिया में सार्क का जन्म 1980 के दशक में यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर हुआ जो सबसे अधिक सकारात्मक कदम था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को संस्थापक रूप 1985 में दिया गया। इस प्रकार इस क्षेत्र में स्थायी रूप से विकासशील संस्था का जन्म सात देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ढाका में हुआ जो वर्तमान में अफगानिस्तान के सदस्य बनते हैं। बढ़कर आठ हो गयी है तथा यह निश्चित किया गया कि सार्क सम्मेलन प्रतिवर्ष सम्बन्धित देशों की राजधानियों में बारी–बारी से होगा तथा विदेश मंत्री कम से कम दो बार सार्क मंच पर एकत्रित होंगे, जिसका परिणाम भी सकारात्मक निकला। अब द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर विकसित प्रतीत होता है तथा सभी सदस्य देश इस दिशा में सहयोग करने हेतु अग्रसर हैं।

अतः अब तक सार्क 27 वर्ष पूरा कर चुका है। लगभग 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली है परन्तु सार्क की तुलना में यूरोपीय यूनियन, आसियान एक शक्तिशाली आर्थिक परिसंघ के रूप में कार्य कर रहे हैं परन्तु सार्क ने वो मुकाम हासिल नहीं किया इसका प्रमुख कारण इन सार्क देशां में पूँजी का अभाव व संसाधनों की कमी है। अतः राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि भारत–पाक संबंध इसके विकास में मुख्य बाधक हैं। क्योंकि इनकी आंतरिक राजनीतिक समस्याओं ने हमेशा ही सार्क की कार्ययोजनाओं पर प्रभाव डाला है। परन्तु नकारात्मक प्रभाव के बावजूद भी दोनों के संबंधों को सामान्य बनाने में सार्क एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा सदस्य देशों में विकास की संभावना भी तलाश रहा है।

सन्दर्भ

1. अयूब, मोहम्मदः इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश : सर्च फोर ए न्यू रिलेशनशिप (आई0सी0डब्ल्यू0ए0 नई दिल्ली), 1975
2. इतेरवारूज्जमानः साउथ एशियन रीजनल कॉ–आपरेशन हफीज अब्दुल ए सोशियल इकॉनॉमिक एप्रोच टू पीस एण्ड स्टेबिलेटी, (गुलाम मुस्जफा हक्कानी पब्लिशर्स, ढाका), 1985
3. काशिकार मोहनः दक्षेसः इट्स जेनियस् डवलपमेण्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट्स हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई 2000
4. कुरेशी, एम0एल0ः सर्वे ऑफ इकॉनॉमिक एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ साउथ एशिया, (लोटस प्रेस, लि0 कोलम्बो), 1981
5. कॉफले, प्रफुल्ला केः फॉरेन ट्रेड एण्ड रीजनल कॉ–ऑपरेशन, (सी0ई0डी0ए0 त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमाण्डू), 1980
6. खत्री, श्रीधर, (सं0)ः रीजनल सिक्युरिटी इन साउथ एशिया, (सेन्टर फॉर नेपाल एण्ड एशियन स्टडीज, त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज, काठमाण्डू), 1986
7. खॉन जिल उर केः दक्षेस एण्ड द सपुर पॉवर्स, (यूनिवर्सिटी प्रेस लि0, ढाका), 1991
8. गोयल, ओ0पी0ः इण्डिया एण्ड दक्षेस एजेनजमेन्ट्स वोल्यूम–I, ईशा बुक्स, नई दिल्ली, 2004
9. गुप्ता सेनः दक्षेस–आसियान : प्रोस्पेक्ट्स एण्ड प्रोब्लम्स ऑफ इन्टर रिजनल को–ऑपरेशन साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1989
10. जैक्सन, डगलस डब्ल्यू0ए0ः पॉलिटिक्स एण्ड ज्योग्राफिक रिलेशनशिप, (प्रेन्टिस हाल, न्यूजर्सी), 1964
11. जैन बी0एम0 (सं0)ः साउथ एशिया इन द न्यू वर्ल्ड ऑडर आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर, 1994
12. फर्डनिस, उर्मिलाः एथनिसिटी एण्ड नेशनल बिल्डिंग इन साउथ एशिया, (सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली), 1990
13. ब्रासकोय, एन0पी0ः रीजनल इकॉनामिक कॉ–ऑपरेशन इन साउथ एशिया, (नेपालीज पर्सपैक्टिव), (दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली), 1990
14. मिश्रा, पी0के0ः ढाका सम्मिट एण्ड दक्षेस, (के0पी0 वागची एण्ड कंपनी, कलकत्ता), 1986
15. मुनि एस0डी0 मुनि अनुराधाः रीजनल कॉ–आपरेशन इन साउथ एशिया, (नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली), 1984
16. रमाकान्त (सं0)ः रिजनलिज्म इन साउथ एशिया, (आलेख पब्लिशर्स, जयपुर), 1988
17. राघवन, एस0एन0ः मैक्रो इकॉनॉमिक परफार्मेन्स एण्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन दक्षेस कन्ट्रीज–ए रिव्यू, (इन्ट्रेस्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली), 1990
18. वोहरा, दीवान सी0ः इण्डियाज ट्रेड डिप्लोमेसी इन द थर्ड वर्ल्ड, (विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली), 1987
19. शाह पूर्णिताः दक्षेस देशों के बीच सहयोग और संघर्ष, (आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स जयपुर), 2001
20. शरण व्युप्तकेशः इण्डियाज् रोल इन साउथ एशियन रीजनल को–आपरेशन, (कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली), 1991
21. सिंह, घनश्याम, एन (सं0)ः द इकॉनॉमी ऑफ दक्षेस नेशन्स, (अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली), 1993
22. सिंह, जनक बहादुरः दक्षेस ग्रोथ एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स (अशोका प्रिन्टर्स, नई दिल्ली), 1989